"कन्सर्न ओवर पब्लिक सैक्टर फैलियर" शीर्षक वाला समाचार

2020. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 मार्च, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कन्सर्न ओवर पब्लिक सैक्टर फेलियर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1985 में रतन टाटा की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सरकारी क्षेत्र में चलायी जा रही परियोजनाओं की प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) श्री रतन एन० टाटा की अध्यक्षता में गठित परियोजना कार्यान्वयन सलाहकार परिषद् ने अपनी रिपोर्ट में (क) परियोजना कार्यान्वयन प्रणाली में सुधार और (ख) संगठनात्मक विकास का उल्लेख किया है, जिसकी फिलहाल, सरकार के विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है, इस स्तर पर विषय वस्तु को बताना जन हित में नहीं होगा।

नाभिकीय विद्युत केन्द्रों की स्थापना

2021. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाभिकीय विद्युत निगम द्वारा देश में और अधिक विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इन सभी प्रस्तावों की स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन की स्थापना हाल ही में हुई है। तथापि, सरकार ने सिद्धांत रूप से यह लक्ष्य अनुमोदित कर दिया है कि सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता वाले बिजलीघर लगा दिए जाएं, जिनमें 235 मेगावाट और 500 मेगावाट क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टर शामिल होंगे।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति ने देश के सभी क्षेत्रों में स्थित स्थलों का अध्ययन परमाणु बिजलीघर लगाने की दृष्टि से किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

"प्लानर्स ब्लेम्ड फार शार्टेज" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार

2022. **श्री रशीद मसूद :**
श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1988 के इकानामिक टाइम्स में "प्लानर्स ब्लेम्ड फार शार्टेज" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है इंडियन केमिकल्स एंसीलरीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया है कि योजना बनाने वालों के अदूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण देश के अनेकों उद्योग आज भी अनिश्चितता और आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरेन सिंह इंगती): (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित समाचार का अवलोकन किया गया है। प्रेस रिपोर्ट की विषयवस्तु को नोट कर लिया गया है, लेकिन सरकार, उसमें व्यक्त किए गए कुछ विचारों और दिए गए कुछ तथ्यों से सहमत नहीं है। आर्थिक आयोजन का लक्ष्य कमियों को दूर करना और अन्तर-क्षेत्रकीय संतुलन को बनाए रखना है।

पाकिस्तान द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप

2023. **श्री रशीद मसूद : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद कि पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा है और भारत के आंतरिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप कर रहा है, सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर पाकिस्तान की सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में उग्रवादी तत्वों को पाकिस्तान से निरंतर सहायता मिलने के सवाल को पाकिस्तान की सरकार के साथ अनेक अवसरों पर विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। दिसम्बर, 1986 में दोनों देशों के गृह सचिवों की पिछली बैठक में भी इस विषय पर विस्तार से बातचीत हुई थी।

(ग) पाकिस्तान की सरकार ने बार-बार इस बात की पुष्टि की है कि वह भारत में उग्रवादी तत्वों को कोई सहायता नहीं देगी।

परमाणु विद्युत केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने की योजना

2024. **श्री रशीद मसूद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस शताब्दी के अंत तक वर्तमान परमाणु विद्युत केन्द्रों की क्षमता 1230 मेगावाट से बढ़ा कर 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नाभिकीय विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक श्री एस० एल० कटि ने उक्त लक्ष्य की प्राप्ति में आशंका व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय 6 यूनिट काम कर रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 1230 मेगावाट है। 8 ऐसे यूनिटों का निर्माण-कार्य